

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 253] नई दिल्ली, शनिवार मई 20, 1972/वैशाख 30, 1894

No. 253] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 20, 1972/VAISAKHA 30, 1894

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 20th May 1972

S.O. 365(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 725, dated the 4th March, 1966 (hereinafter referred to as the said Order), read with the Order of the Government of India in the Ministry of Foreign Trade No. S.O. 103, dated the 2nd January, 1971, the management of the whole of the industrial undertaking known as the Hira Mills Limited, Ujjain had been taken over by the Authorised Controller referred to therein for a period upto and inclusive of the 3rd March, 1972;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period of two years;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and of all other powers hereunto enabling, the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of 3rd March, 1974.

[No. F. 7(55)/70-TEX(G).]

K. KISHORE, Joint Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 मई, 1972

का० आ० 365(अ).—यतः भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 103, दिनांक 2 जनवरी, 1971 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 725, दिनांक 4 मार्च, 1966 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा होरा मिल्स लिमिटेड, उज्जैन नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उसमें निर्दिष्ट प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा 3 मार्च, 1972 तक के लिए, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, ग्रहण कर लिया गया था ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए प्रभावी बना रहे;

अतः अब, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त आदेश का प्रभाव 3 मार्च, 1974 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, और बना रहेगा ।

[सं० फ० 7(55)/70-टैक्स (जी)]

के० किशोर,

संयुक्त सचिव ।